MR. SPEAKER: I have already told you . . .

SHRI JYOTIRMOY BOSU: You observed the other day . . . **

MR. SPEAKER: Don't record.

Mr. Kanwar Lal Gupta.
(*Interruptions*) **

MR. SPEAKER: Don't record anything.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

REPOTRED INCREASE IN PRICES OF VANASPATI

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar): I call the attention of the Minister of Commerce, Civil Supplies and Co-operation to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

'Reported increase in the prices of Vanaspati.'

वाणिज्य, नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण कुमार गोयल) : महोदय, मैं वनस्पति के मूल्यों में कथित वृद्धि के सम्बन्ध में एक वक्तव्य देने जा रहा हूं ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते ही हैं, एक अनौपचारिक स्वैच्छिक व्यवस्था के अन्तर्गत पहली नवम्बर, 1977 से वनस्पति का कारखाना मूल्य 140 रुपये प्रति 16.5 किलो ग्राम टिन (जिसमें उत्पादन शुल्क तो शामिल था लेकिन स्थानीय कर शामिल नहीं थे) निर्धारित किया गया था । इस व्यवस्था के अन्तर्गत अभी हाल ही तक वनस्पति के मूल्य कमोबेश स्थिर रहे हैं । वनस्पति उद्योग को उसकी लगभग 80 प्रतिशत आवश्यकता के लिए आयातित तेल दिये जाते हैं और इन आयातित तेलों की लागत पिछले कुछ महीनों के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय मण्डियों में खाद्य तेलों के मूल्यों में हुई भारी वृद्धि तथा इन पर लगाये गये आयात शुल्क के कारण बढ़ी है । इसलिये राज्य व्यापार निगम द्वारा वनस्पति उद्योग को दिये जाने वाले आयातित तेलों के मूल्य में वृद्धि करनी पड़ी है । परिणामस्वरूप वनस्पति के कारखाना मूल्य बढ़े हैं । मूल्यों के बढ़ने की सूचना मिली है और यह बताया गया है कि 16.5 किलोग्राम के टिन के कारखाना मूल्य 155 रुपये से 160 रुपये के बीच चल रहे हैं ।

वनस्पति उद्योग की एसोसिएशनों से वनस्पति के कारखाना मूल्य में वृद्धि करने के लिए सुझाव प्राप्त हुए हैं । इनकी जांच की जा रही है ।

आयातित तेलों के मूल्यों में हुई वृद्धि और दूसरी सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुये, वनस्पति के मूल्यों को उचित स्तर पर रखने के लिये आवश्यक उपाय किए जाएंगे ।

श्री राज नारायण : (रायबरेली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है . . .

(*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are an old and experienced member. The point of order must relate to a subject before the House. The subject before the House is Calling Attention.

SHRI RAJ NARAIN: आप इतना ही साफ कर दीजिये कि अपील और इंटरवेंशन में कोई फर्क है ? Is there any

*Not recorded.

difference between Appeal and Intervention? इतना ही कलिंग मैं आप से चाहता हूं ।

MR. SPEAKER: That is not point of order. I do not give legal advice. I have stopped giving legal advice.

श्री राज नारायण : आप इतनी बात पहले कह देते तो मामला खत्म हो जाता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री कंवर लाल गुप्त :

श्री कंवर लाल गुप्त : मैंने मंत्री महोदय के सारे वक्तव्य को पढ़ा है और पढ़ने के बाद मैं समझता हूं कि यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वनस्पति घी के दाम पंद्रह मार्च से अभी तक एक टीन पर बीस रुपये बढ़ गए हैं । यह शाकिंग है और कंज्यूमर्ज पर बहुत बड़ा ब्लो है । वनस्पति घी हर घर में इस्तेमाल होता है । एक टिन पर केवल पद्रह दिन में बीस रुपया बढ़ जाना बहुत जबर्दस्त चीज है और बड़ा भारी ब्लो है । इसके उन्होंने अपने ब्यान में दो कारण बताए हैं । एक तो यह बताया है कि बजट में ड्यूटी पांच प्रतिशत बढ़ा दी गई है और दूसरे उन्होंने कहा है कि इंटरनैशनल प्राइसिस चूंकि तेल की बढ़ गई है और विदेशी तेल चूंकि अस्सी प्रतिशत कंज्यूम होता है यहां पर इसलिए वनस्पति घी के दाम बढ़े हैं । मैं जानना चाहता हूं कि क्या इंटरनैशनल प्राइसिस भी इस हद तक बढ़ी हैं एक टिन पर कि उसके दाम इतने आपको बढ़ाने पड़ गए हैं ? मैं समझता हूं कि इंटरनैशनल प्राइसिस जो हैं वे इस हद तक नहीं बढ़ी हैं । एस० टी० सी० और मिल मालिक दोनों मिल करके मुनाफाखोरी कर रहे हैं और कंज्यूमर को हिट कर रहे हैं । आप मेहरबानी कर के वाइफ़रकेशन करके बताइये कि दुनिया में इंटरनैशनल मार्केट में तेल के दाम कितने बढ़े और ऐक्साइज ड्यूटी एक टिन पर कितनी बढ़ी और उसके बाद मिल मालिकों ने कितना बढ़ाया । तब उसकी जस्टीफिकेशन होगी ।

मुझे याद है कि एस० टी० सी० पहले 6,100 रु० पर टन देती थी इसको और उसके बाद अभी जो देती है 7,585 रु० यानी 1,485 रु० पर टन उन्होंने दाम बढ़ा दिये । तो इंटरनेशनल मार्केट में....

श्रीमती मृणाल गोरे (बम्बई-उत्तर) : ड्यूटी कम की है अभी ।

श्री कंवर लाल गुप्त : 1,500 रु० एस० टी० सी० ने बढ़ाये । इसका कोई जस्टीफ़िकेशन नहीं है । इंटरनैशनल मार्केट में इतनी कीमत नहीं बढ़ी है । इसके पहले साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी लगी थी तब भी वही दाम बढ़े, और अब 5 परसेंट है तब भी वही दाम हैं और एक मिल की ऐक्स फैक्ट्री प्राइस 107 रु० है और कंज्यूमर प्राइस 175 रु० और दूसरी मिल ने 5 रु० एक टिन में कम की है, गणेश मिल ने । तो इसके पहले आपको याद होगा जनवरी और फ़रवरी के महीने में जितनी मिलें थीं वनस्पति घी की जो आपने इनफ़ोरमल प्राइस तय की थी उससे कम दाम में बेचती थीं । वनस्पति इंडस्ट्री ने दो, तीन साल जितनी मुनाफ़ाखोरी की, मैं समझता हूं कि 30 साल के रेकार्ड में नहीं की और आप लोग सोते रहे, और यहां तक कि जो दाम आपने फ़िक्स किये थे उससे 4, 5 रु० प्रति टिन कम में वह स्वयं बेच रहे थे । आपने कुछ नहीं किया । तो उसकी वजह से जो और चीजों के दाम हैं, जो इंडिजिनस तेल है, उसके दाम बढ़ गये और खाने के तेल के दाम 1,000, 1,200 रु० टन बढ़ा दिये हैं, जिसका कोई जस्टीफ़िकेशन नहीं है ।

तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पहले तो आप बाइफ़रकेशन कीजिये और बताइये कि इंटरनैशनल मार्केट में पहले 15 मार्च, को क्या प्राइस थी और अब क्या प्राइस है ? और 1,400, 1,500 रु० प्रति टन बढ़ गई है । ऐक्साइज में जो 20 रु० टन आपने बढ़ाया साढ़े 12 से 5 परसेंट

कर दिया तो उस पर कितना बढ़ा ? और जो पहले फ़रवरी के महीने में रिडक्शन पर बेचते थे, 5 रु० टिन खुद कम करके बेचते थे तो वह अगर एब्जार्ब कर लिया जाये तो भी 20 रु० टिन का कोई जस्टीफ़िकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि आज तक 30 साल में इतनी कीमत कभी नहीं बढ़ी। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसका बाइफ़रकेशन क्या है, जस्टीफिकेशन क्या है ? और क्या वह सदन को विश्वास दिलाएंगे इसकी कॉस्टिंग करके कितना दाम पड़ता है पहले से? क्योंकि पहले भी बहुत मुनाफ़ाखोरी हो रही थी। उससे अब कितनी कॉस्टिंग होती है, और कितने में कंज्यूमर को मिलना चाहिये ? और साथ ही जो दूसरे तेलों के दाम बढ़े हैं, हिन्दुस्तान में उनको कंट्रोल करने के लिये आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ?

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य का बहुत ही आभारी हूं कि उन्होंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से वनस्पति तेल की कीमतों के सम्बन्ध में सरकार का और सदन का ध्यान आकर्षित किया है। और एक दम 140 रु० से 160 रु० यानी 20 रु० प्रति टिन, जिसकी कि मात्रा 16.5 किलो होती है, उस पर इतनी बढ़ोतरी होना हर एक व्यक्ति के लिये चिन्तित होना स्वाभाविक और आवश्यक है।

श्री कंवर लाल गुप्त : अनपैरलल है।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अनपैरलल इसलिये नहीं कहा जा सकता है कि जिस समय इस वनस्पति पर कंट्रोल था जिसको कि खत्म किया है 5 फरवरी, 1975 को उस समय प्राइस कंट्रोल के समय में 168 रु० 23 पैसे प्रति टिन उत्तरी क्षेत्र में कीमत थी। लेकिन यह कहकर मैं इसको जस्टीफाई नहीं करना चाहता कि जो कुछ किया गया, वह ठीक किया गया है।

मैं पहले तो माननीय सदस्य के आंकड़ों में थोड़ा-सा सुधार करना चाहूंगा। इस समय जो एस० टी० सी० अपना इम्पोर्टेड आयल सप्लाई कर रही है वह 80 परसेंट है लेकिन साथ-साथ हमारे हिन्दुस्तान में पैदा होने वाले तिलहनों को भी प्रोत्साहन मिल सके, यह व्यवस्था की है कि अगर कोई वनस्पति के उत्पादक वनस्पति के उत्पादन में सिवाय मूंगफली और सरसों के तेल कोई दूसरे खाद्यान्न तिलहनों, जिसमें 5 प्रतिशत तिल का होना आवश्यक है, बाकी 95 प्रतिशत इंडीजिनस आयल लेना चाहें तो उनको वह एलाऊ किया है। लेकिन इसके बाद भी स्थिति यह है कि 80 प्रतिशत आयातित तेल वनस्पति मैन्युफैक्चरर्स को उनकी आवश्यकता के अनुरूप देना पड़ता है।

अभी तक आयातित तेल का मूल्य 6100 रुपये प्रति टन था। अब जो उनको आयल सप्लाई किया जा रहा है 14 मार्च से उसका मूल्य 7585 रुपये न होकर 7250 रुपये प्रति टन है। माननीय सदस्य ने जो 7585 के फिगर्स कहे हैं, वह भी निराधार नहीं हैं। उसमें सत्यता केवल इतनी ही है कि जैसे ही बजट में साढ़े 12 परसेंट ड्यूटी घोषित हुई थी, उसी आधार पर यह प्राइस तय की थी लेकिन 17 तारीख को जब बजट में दोबारा ड्यूटी कम करने की घोषणा की गई तो उस समय वह प्राइस 7250 रुपये की गई है। तो 6100 रुपये जो हमारी इश्यू प्राइस थी 80 परसेंट रिक्वायरमेंट के अगेन्स्ट वह अब 7250 रुपये की गई है।

जहां तक माननीय सदस्य ने इसके ब्रेक-अप के बारे में पूछा है, मैं बताना चाहूंगा कि एस० टी० सी० ने इस 7250 रुपये के मूल्य को जो आंका है, वह कोई एड-हाक नहीं है, मनमाने ढंग से नहीं है। इस मूल्य को आंकने के लिये एक कमेटी है, जिसमें एस० टी० सी० के अधिकारी और उनके अतिरिक्त सिविल सप्लाईज, कामर्स और

[श्री कृष्ण कुमार गोयल]

फाइनेन्स मिनिस्ट्री के रिप्रेजेन्टेटिव्ज भी हैं, और यह 5 व्यक्तियों की कमेटी मिलकर मूल्यों का निर्धारण करती है कि एस० टी० सी० के आयातित आयल के इश्यू प्राइसेस क्या होने चाहियें। जहां तक ब्रेक-अप का सवाल है, हमने 3, 4 तरह से मूल्य आंके हैं। पहले तो 1-3-79 को हमारे एस० टी० सी० के स्टाक में जितना आयल था, उसका जो मूल्य आया, उसको हमने आंका है। क्योंकि उस पर विदेशी मार्केट में इस समय के बढ़े हुए मूल्यों पर पैसे नहीं देने पड़े, बढ़ा हुआ किराया नहीं देना पड़ा, इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ी, तो जो 1-3-79 को स्टाक था, उसके मूल्य से आंका गया है। उसके बाद 5-3-79 तक विश्व के बाजार में जो हमने तेल के सौदे किये, उनका जो मूल्य आया और उसकी जो लैंडेड कास्ट होगी, उसको आंका है और इसके बाद बीच में जब साढ़े 12 परसैंट ड्यूटी की घोषणा की गई थी, हमारे 3 जहाज इस इम्पोर्टेड आयल को लेकर बन्दरगाहों पर आ चुके थे और उनके आने के बाद उतारने के बाद हमको साढ़े 12 परसैंट ड्यूटी देनी पड़ी।

उसको रिफण्ड नहीं किया, वह ड्यूटी रिफण्डेबिल नहीं है। इस प्रकार से इन सारे आंकड़ों को उतारने के बाद यह प्राइस तय की गई है: 7250 रुपये। 6,100 रुपये के एगेंस्ट 7,250 रुपये हमारी इस्यू प्राइस है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा है, जो प्राइस तय को गई थी, वह भी टैरिफ कमीशन के फार्मूले को आधार बना कर कास्टिंग कर की गई थी। माननीय सदस्य को याद होगा कि आरम्भ में मार्केट में प्राइस 158 रुपये थी। नवम्बर, 1977 से ले कर 158 रुपये की प्राइस को 140 रुपये पर लाया गया था। कोई स्टेचुटरी कण्ट्रोल नहीं है। एस०टी०सी० जो आयल सप्लाई करता है, उसके मूल्य के आधार पर ये मूल्य तय होते हैं। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 20 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, हम उससे सैटिसफाइड नहीं हैं। दोनों एसोसियेशन्ज अपने अपने आर्ग्युमेंट्स दे रही हैं। इस महीने के अन्त तक इन दोनों एसोसिएशन्स को यहां बुलायेंगे। या तो वे इनफार्मल वालन्टेरी एग्रीमेंट से प्राइस पर एग्री होंगी, अन्यथा सरकार के पास जो कठोर से कठोर अधिकार हैं, वह उनका यथासम्भव प्रयोग करने के लिए पीछे नहीं हटेगी। मैं माननीय सदस्यों से अप्रैल के अन्त तक का समय मांगता हूं। (व्यवधान)

श्री श्याम सुन्दर लाल (बयाना): अध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय एक बहुत अच्छे वकील हैं। राजस्थान में उनकी अच्छी वकालत रही है। एक अच्छे वकील का काम है कि चाहे कितना भी घटिया केस हो, उसको वह इस ढंग से रखे कि वह बिल्कुल सही मालूम हो। जो कीमत बढ़ी है, उसको उन्होंने जस्टिफाई किया है और कहा है कि वह बिल्कुल ठीक है। उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं, वे बिल्कुल गलत हैं। शायद उन्होंने वनस्पति घी खरीदा नहीं है। आज की तारीख में चार किलो का टीन 49 रुपये और कुछ पैसे का मिलता है। शायद वह डाल्डा खाते नहीं हैं, देसी घी खाते हैं। अगर वह वनस्पति घी खरीदें, तो उन्हें पता लगे। (व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार, और विशेषकर हमारे मन्त्री महोदय, इस बारे में क्या करने जा रहे हैं। क्या उन्होंने मैनु-फेक्चरर्ज से बातचीत की है, अगर नहीं, तो क्या वह उनके खिलाफ एम०आर०टी०पी०सी० से एनक्वायरी करवा रहे हैं? क्या गवर्नमेंट खुद उनकी मिलों को टेक-ओवर कर रही है, अगर नहीं, तो क्या कम से कम गरीब आदमियों के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम गवर्नमेंट अपने हाथ में ले रही है।

उन्होंने जो कई बातें बताने की कोशिश की हैं, मैं उन में नहीं जाना चाहता हूं ।

तू इधर-उधर की बात न कर,
यह बता कि काफिले क्यों लुटे,
मुझे रहजनों से गर्ज नहीं,
तेरी रहबरी से सवाल है ।

वह मिनिस्टर हैं ; वह बतायें कि गरीबों को वनस्पति घी कम कीमत पर कैसे मिलेगा । वह वकालत कर रहे हैं कि यहां से आया, वहां से आया । हमारे पास लोग आते हैं, हम उन्हें कैसे समझायें कि जनता पार्टी के राज्य में पन्द्रह दिनों में कीमतें इतनी कैसे बढ़ गई । इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि लोगों को कब से सही कीमत पर वनस्पति घी मिलेगा, इसके लिए सरकार का क्या ठोस प्रोग्राम है और वह इस बारे में क्या कदम उठाने जा रही है ।

श्रीकृष्ण कुमार गोयल : जैसा कि मैंने कहा है, मैं व्यापारियों के इस कृत्य का समर्थन नहीं करता हूं । बल्कि, इसकी आलोचना और भर्त्सना करता हूं । केवल एस०टी०सी० ने जो आयातित तेल का मूल्य बढ़ा कर सप्लाई करना शुरू किया है, उसने जो मूल्य बढ़ाया है, मैं ने केवल उसको जस्टिफाई किया है । वनस्पति मैन्युफेक्चरर्स के दो एसोसिएशन्स हैं वी०एम०ए० और आई०वी०पी०ए०, दोनों के रिप्रेजेन्टेशंस आए हैं । स्वयं कामर्स मिनिस्टर ने इन को बुला कर इस सम्बन्ध में दो टूक जवाब दे दिया है और साफ कह दिया है कि आप अपनी कास्टिंग ले कर आइए, मैं 160 रुपये के प्राइस को ऐग्री नहीं करता । दोनों ओर से कास्टिंग आई हैं । उस पर प्रोसेसिंग हो रही है । मैं आप को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार जिस भी कदम को उठाने की आवश्यकता होगी उठाएगी । चाहे जैसा श्री लाल ने कहा डिस्ट्रीब्यूशन के सम्बन्ध में हो या स्टेचुटरी प्राइस के सम्बन्ध में हो, जैसा भी कदम उठाने की आवश्यकता होगी सरकार उठाएगी लेकिन इस को हमें जांच करने की जरूरत है ।

12.36 hrs

PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

HUNDRED AND TWENTIETH REOPRT

SHRI P. V. NARASIMHA RAO (Hanamkonda): I beg to present the Hundred and twentieth Report of the Public Accounts Committee on Action Taken by Government on the recommendations contained in their Twelfth Report (Sixth Lok Sabha) on New Lines and Line Capacity Works.

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

TWENTY-FIRST AND TWENTY-SECOND REPORTS

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings:—

(1) Twenty-first Report on Action taken by Government on the recommendations contained in the First Report of the Committee (Sixth Lok Sabha) on Extravagant and Infructuous Expenditure on Entertainment by Public Undertakings.

(2) Twenty-second Report on Action Taken by Government on the recommendations contained in the Tenth Report of the Committee (Sixth Lok Sabha) on Unusually High Expenditure by Public Undertakings for their Head Offices.